बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 23 ● अंक: 229 ● नई दिल्ली ● शुक्रवार 12 सितम्बर 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

पीड़ित परिवार को मिलेगा 2.5 करोड़ का मुआवजा, सड़क हादसे में हुई थी डॉक्टर की मौत

दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने मई 2023 में ओखला में हुई सड़क दुर्घटना में मारे गए एक डाक्टर के परिवार को 2.5 करोड़ रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए है। न्यायाधिकरण की पीठासीन अधिकारी शैली अरोड़ा ने कहा कि मृत्यु की स्थिति में दावेदारों के कानूनी वारिस किसी अप्रत्याशित लाभ की उम्मीद नहीं कर सकते। साथ ही दिया गया मुआवजा किसी मानवी के बदले नहीं होता। बताया गया कि मृतक यासीन खान 30 वर्षीय सीनियर रेजिडेंट डाक्टर थे, जो हर महीने 1.4 लाख रुपये कमाते थे। उनके पीछे उनकी पत्नी, माता-पिता और दो नाबालिग बेटे हैं।

मामूली गिरावट के साथ खुला घरेलू शेयर बाजार, बाद में पकड़ी रफ्तार; हरे निशान पर सेंसेक्स-निफ्टी

नई दिल्ली । अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से अगले सप्ताह ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद के बीच एशियाई बाजारों में तेजी देखी गई। इसके चलते गुरुवार को शुरुआती कारोबार में बेंचमार्क इक्विटी सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता के सफल समापन को लेकर नए उत्साह ने भी बाजारों को सकारात्मक दायरे में बने रहने में मदद की। शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 153.82 अंक चढ़कर 81,578.97 पर पहुंच गया।

ऐसे ही 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 34.15 अंक बढ़कर 25,007.25 पर आ गया।

किसे फायदा-किसे नुकसान?

सेंसेक्स की कंपनियों में इटरनल, अदाणी पोर्ट्स, एनटीपीसी, बजाज फाइनेंस, भारतीय स्टेट बैंक और बजाज फिनसर्व हरे निशान पर दिखाई दिए। हालांकि, इंफोसिस, टेक महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट और कोटक महिंद्रा बैंक पिछड़ते नजर आए। एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, बुधवार को एक दिन की राहत के बाद विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 115.69 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। हालांकि, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने पिछले दिन 5,004.29 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

एशियाई और अमेरिकी बाजारों का हाल

एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी, जापान का निक्केई 225 सूचकांक और शंघाई का एसएसई कंपोजिट सूचकांक सकारात्मक दायरे में कारोबार कर रहे थे, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग कमजोर रहा। अमेरिकी बाजार बुधवार को मिले-जुले रुख के साथ बंद हुए थे। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.07 प्रतिशत गिरकर 67.44 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजयकुमार ने कहा, भारत के लचीले मैक्रो-इकोनॉमिक परिदृश्य और इस साल लागू किए गए व्यापक सुधारों, खासकर जीएसटी सुधारों ने अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व वृद्धि के शिखर पर पहुंचा दिया है। मेहता इक्विटीज लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (शोध) प्रशांत तापसे ने कहा, अमेरिका-भारत व्यापार समझौते की उम्मीद और अमेरिका में कमजोर पीपीआई के कारण एसएंडपी 500 और नैस्डैक के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचने से तेज रफ्तार बरकरार है।

बीते दिन कैसा था बाजार हाल?

इससे पहले बुधवार को सेंसेक्स 323.83 अंक या 0.40 प्रतिशत चढ़कर 81,425.15 पर बंद हुआ था। यह लगातार तीसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ था। ऐसे ही निफ्टी 104.50 अंक या 0.42 प्रतिशत बढ़कर 24,973.10 पर पहुंच गया था।

अमित शाह ने पांच और एयरपोर्ट पर शुरू किया फास्ट ट्रैक इमीग्रेशन, अब 12 हवाई अड्डों पर मिलेगी सुविधा

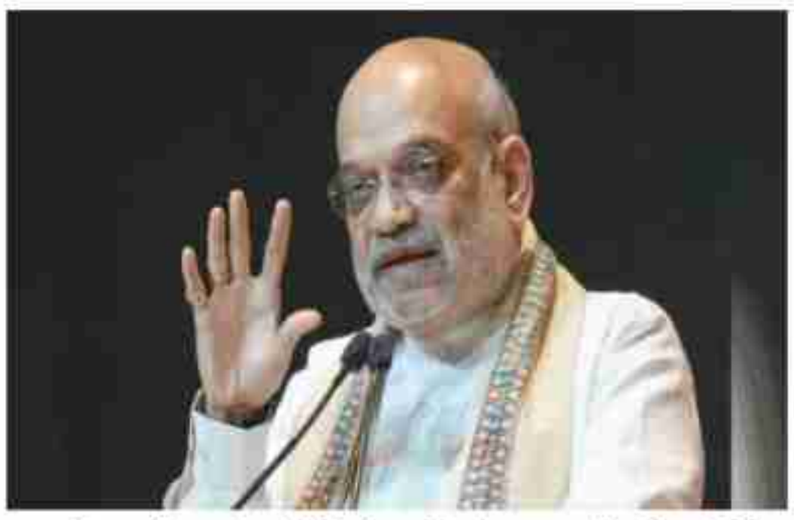

नई दिल्ली ।केंद्र सरकार ने यात्रियों के लिए हवाई सफर को और आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गुरुवार को 'फास्ट ट्रैक इमीग्रेशन-ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम' (एफटीआई-टीटीपी) को देश के पांच और हवाई अड्डों पर शुरू किया। इस योजना के तहत भारतीय नागरिकों और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्डधारकों को इमीग्रेशन प्रक्रिया में लंबी कतारों से छुटकारा मिलेगा और वे ई-गेट से जल्दी क्लियरेंस पा सकेंगे। यह योजना सबसे पहले जुलाई 2024 में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू हुई थी। इसके बाद दो महीने में इसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बंगलूरू, हैदराबाद, कोचीन और अहमदाबाद में लागू किया गया। अब इस सुविधा को लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, तिरुचिरापल्ली, कोझिकोड और अमृतसर एयरपोर्ट पर भी लागू कर दिया गया है। गृहमंत्री शाह ने वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान कहा कि फास्ट ट्रैक इमीग्रेशन से यात्रियों को तेजी, सुरक्षा और बिना परेशानी के अंतरराष्ट्रीय सफर का अनुभव मिलेगा। अभी तक तीन लाख लोगों ने इस योजना के लिए पंजीकरण कराया है, जिनमें से करीब 2.65 लाख यात्रियों ने इस सुविधा का लाभ भी उठाया है।

कैसे करेगा काम?

योजना के तहत यात्री ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें पासपोर्ट की न्यूनतम वैधता छह महीने होनी चाहिए। आवेदन स्वीकृत होने के बाद यात्री को बायोमेट्रिक विवरण (फिंगरप्रिंट और चेहरे की तस्वीर) देने के लिए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे या नजदीकी विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) जाना होगा। सफल सत्यापन के बाद यात्री को व्हाइट लिस्ट ऑफ ट्रस्टेड ट्रैवलर्स में शामिल किया जाएगा।

अमेरिका की तर्ज पर बनी योजना

अधिकारियों के मुताबिक यह योजना अमेरिका के ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम की तर्ज पर बनाई गई है। वहां पहले से अनुमोदित यात्रियों को देश में प्रवेश के समय तेजी से क्लियरेंस मिलती है। भारत में भी अब इस व्यवस्था के जरिए यात्रियों को ई-गेट से गुजरने पर तुरंत इमीग्रेशन क्लियरेंस मिल जाएगा।

21 एयरपोर्ट तक विस्तार की योजना

केंद्र सरकार की योजना है कि इस प्रोग्राम को चरणबद्ध तरीके से देश के 21 बड़े हवाई अड्डों तक पहुंचाया जाए। पहले चरण में भारतीय नागरिकों और ह्यूद्ध कार्डधारकों को सुविधा दी जा रही है। दूसरे चरण में इसे विदेशी यात्रियों तक बढ़ाया जाएगा। इस कार्यक्रम को लागू करने की जिम्मेदारी ब्यूरो ऑफ इमीग्रेशन के पास होगी। शुरुआती चरण में यह योजना बिल्कुल मुफ्त है। यात्रियों को किसी अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। गृहमंत्रालय ने यात्रियों के लिए एक हेल्पडेस्क ईमेल आईडी भी जारी की है, ताकि उन्हें आवेदन या प्रक्रिया में किसी तरह की दिक्कत हो तो मदद मिल सके।

दिल्ली में मौसम ने बदला मिजाज, तेज हवाएं कर सकती हैं परेशान, एयर पॉल्यूशन में सुधार

नई दिल्ली । दिल्लीवासियों के लिए गुरुवार की सुबह राहतभरी रही. राजधानी में आज (11 सितंबर) न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मुताबिक, दिन में सतही हवाएं तेज चलने की संभावना है. मौसम विभाग का कहना है कि इस समय दिल्ली में नमी और तापमान का संतुलन लोगों को उमस से राहत दिला रहा है. तेज हवाएं चलने से दोपहर का मौसम भी थोड़ा सुहावना महसूस होगा. अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. सुबह साढ़े 8 बजे आर्द्रता का स्तर 71 प्रतिशत रिकॉर्ड किया गया. मौसम विभाग के अनुसार, हवा में नमी का यह स्तर सामान्य है. नमी की वजह से सुबह-सुबह हल्की उमस जरूर महसूस हुई, लेकिन तेज हवा ने इसे यादा परेशान नहीं होने दिया. दिल्ली में लंबे समय बाद वायु गुणवत्ता पर अच्छी खबर सामने आई है. आज सुबह 9 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 89 दर्ज किया गया, जो 'संतोषजनक' श्रेणी में आता है. इसका मतलब है कि दिल्ली की हवा फिलहाल लोगों की सेहत के लिए यादा नुकसानदेह नहीं है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक वायु गुणवत्ता सूचकांक को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है. अगर एक्यूआई 0 से 50 के बीच रहता है तो हवा 'अच्छी' मानी जाती है. वहीं 51 से 100 तक का स्तर 'संतोषजनक' माना जाता है. 101 से 200 तक पहुंचने पर हवा की स्थिति 'मध्यम' कहलाती है. 201 से 300 का स्तर 'खराब', 301 से 400 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच होने पर यह 'गंभीर' श्रेणी में आता है. मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों तक दिल्ली के तापमान में यादा उतार-चढ़ाव नहीं होगा. अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. इस दौरान तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिससे राजधानी में मौसम सुहावना बना रहेगा. साथ ही, हवा की रफ्तार बढ़ने से प्रदूषण का स्तर भी घट सकता है और लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है.

दिल्ली एनिमल वेलफेयर बोर्ड की बैठक में बड़े फैसले, रेबीज नियंत्रण और पेट शॉप्स पर सख्ती

नई दिल्ली । दिल्ली सचिवालय में दिल्ली एनिमल वेलफेयर बोर्ड की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने की. जिसमें विकास आयुक्त शूरबीर सिंह, पशुपालन विभाग, एनडीएमसी, एमसीडी और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. बैठक का मुख्य एजेंडा राजधानी के लिए ठोस और प्रभावी पशु कल्याण कार्ययोजना तैयार करना था. बैठक की शुरुआत राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम से शुरूहुई.

आगामी विश्व रेबीज दिवस को ध्यान में रखते हुए राजधानी में व्यापक कदम उठाने का निर्णय लिया गया. इस दौरान कुत्तों की माइक्रोचिपिंग, डॉग बाइट रोकथाम और टीकाकरण प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर सहमति बनी। मंत्री कपिल मिश्रा ने जल्द ही डॉग सेंसस और मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए, ताकि दिल्ली में रेबीज कंट्रोल और कुत्तों की जनसंख्या प्रबंधन को मजबूत किया जा सके.

बैठक में यह फैसला लिया गया कि दिल्ली की सभी पेट शॉप्स का पंजीकरण अनिवार्य होगा. इसके लिए एक विशेष मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया जाएगा, जो नियमों के क्रियान्वयन की निगरानी करेगी. मंत्री ने साफ कहा कि पंजीकरण की प्रक्रिया में किसी तरह की देरी नहीं होगी और क्षेत्रीय समितियों को सक्रिय कर स्थानीय स्तर पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. बैठक में प्रशासनिक और वित्तीय पहलुओं पर भी कई अहम निर्णय लिए गए. दिल्ली एडवाइजरी बोर्ड फॉर एनिमल वेलफेयर से फंड ट्रांसफर करने का प्रस्ताव रखा गया. साथ ही बोर्ड की गतिविधियों को सुचारू बनाने के लिए स्टैंडिंग कमेटी और उप-समितियों का गठन करने, नए स्टाफ की भर्ती करने और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च की मंजूरी दी गई.

पशु कल्याण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा विभाग की मदद से स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया. इसके अलावा बोर्ड के सदस्यों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले प्रशिक्षण व सम्मेलनों में भाग लेने की अनुमति दी गई. साथ ही जल्द ही दिल्ली में एनिमल मार्केट मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई जाएगी. बैठक के दौरान मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि पिछली सरकार ने वर्षों तक एनिमल वेलफेयर बोर्ड की बैठकें आयोजित नहीं कीं, जिससे कार्यों की गति धीमी हो गई थी. अब सरकार तेजी से काम करेगी और हर जिले में एनिमल वेलफेयर समितियों का गठन होगा. उन्होंने कहा कि पेट शॉप्स पर सख्ती बरती जाएगी और सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता फैलाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे.

पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर भाजपा का सेवा पखवाड़ा, देशव्यापी तैयारियां जोरों पर

नईदिल्ली।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में पंद्रह दिवसीय सेवा पखवाड़ा की तैयारियाँ जोरों पर हैं। भारतीय जनता पार्टी देश भर में केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान और प्रदर्शनियाँ आयोजित करने की योजना बना रही है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पार्टी यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी कि लाखों लोग रक्तदान शिविरों से लाभान्वित हों। पार्टी नेता बंसल ने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन से लेकर गांधी जयंती तक, हम कई गतिविधियाँ करने जा रहे हैं। आयोजित होने वाले सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक रक्तदान शिविर होगा। दूसरा, 17 सितंबर से ही स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। भाजपा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि लाखों लोग इस शिविर से लाभान्वित हो सकें। स्वच्छता अभियान के बारे में, बंसल ने बताया कि वे इस पहल में लोगों को शामिल करने के लिए काम करेंगे और उनसे रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों, स्कूलों और सड़कों की सफाई के लिए स्वयंसेवा करने का आग्रह करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि तीसरा अभियान स्वच्छता अभियान है जो हर साल आयोजित किया जाता है। ऐसे कई स्थान हैं, बस स्टैंड, चौराहा, स्कूल, रेलवे स्टेशन, गलियाँ, हर जगह भाजपा इस बड़ी पहल का आयोजन करेगी। भाजपा नेता ने कहा कि देश भर में विभिन्न प्रदर्शनियाँ आयोजित की जाएँगी, जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्र की सेवा के लिए वर्षों से किए गए कार्यों को प्रदर्शित करेंगी। प्रदर्शनी के साथ-साथ, एक प्रबुद्ध सम्मेलन और अपने-अपने क्षेत्रों के प्रतिष्ठित लोगों के साथ विभिन्न संवाद आयोजित किए जाएँगे। बंसल ने कहा कि देश भर में प्रधानमंत्री द्वारा वर्षों से किए गए कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। 17 सितंबर को प्रदर्शनी लगाई जाएगी, और लोग उनके द्वारा किए गए कार्यों से अवगत होंगे। सेवा पखवाड़े में देश भर में एक प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही, लोगों के साथ विज्ञान, कला, साहित्य, खेल आदि जैसे क्षेत्रों में विभिन्न लोगों को उजागर करने के लिए एक संवाद भी किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत की राजनीति में स्वच्छता और सेवा जैसे मूलभूत मूल्यों को लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा की।

सत्ता पलट और दक्षिण एशिया की राजनीति-एक अंतरराष्ट्रीय विश्लेषण

अब नेपाल भी उसी राह पर चलते हुए सत्ता पलट की कगार पर पहुंच गया है। इसका सीधा संकेत है कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद से जूझ रहे समाजों में युवा अब चुप बिल्कुल नहीं बैठेंगे। साथियों बात अगर हम नेपाल के इस पूरे घटनाक्रम में सोशल मीडिया की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होने की करें तो, नेपाल की लगभग 87 प्रतिशत आबादी मोबाइल इंटरनेट का उपयोग करती है, जबकि 62 प्रतिशत लोग सक्रिय रूप से फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। ट्विटर और यूट्यूब पर भी युवा लगातार अपने विचार साझा कर रहे हैं।

नेपाल में पिछले कुछ दिनों में घटित राजनीतिक घटनाक्रम ने पूरे दक्षिण एशिया को हिला दिया है।भ्रष्टाचार और परिवारवाद से त्रस्त जनता, खासकर युवाओं के जबरदस्त आक्रोश ने मात्र 36 घंटे में सत्ता की गद्दी हिला दी। पाँच पूर्व प्रधानमंत्रियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों ने स्थिति को और अधिक उग्र बना दिया। सत्ता पलट की इस तेज़ी ने यह संकेत दिया है कि नेपाल की जनता अब किसी भी कीमत पर अपारदर्शी शासन स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जिस प्रकार आम लोग और युवा सड़कों पर उतरे, उसने यह साफ कर दिया कि दक्षिण एशिया में लोकतंत्र तभी जीवित रह सकता है जब वह जनता के विश्वास पर आधारित हो। नेपाल की कुल जनसंख्या का लगभग 20 प्रतिशत यानी 62 लाख लोग युवा है, और यही वर्ग देश की राजनीति का भविष्य तय करने वाला है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि वैश्विक स्तर पर भी यह बात स्पष्ट है कि, किसी भी देश का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी के हाथों में होता है। नेपाल के युवाओं ने इस बार भ्रष्टाचार और पारिवारिक राजनीति के खिलाफ अपनी ताकत दिखाकर पूरे विश्व को एक सशक्त संदेश दिया है कि अब युवा पीढ़ी नेपो बेबीज यानी नेताओं के बच्चों और वंशवाद की राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेगी। युवाओं की इस ऊर्जा ने नेपाल की राजनीति को हिला कर रख दिया है और यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या जनरेशन-ज़ेड (जेन ज़ेड) अब नेपाल का नया इतिहास लिखने जा रहा है? साथियों बात अगर हम नेपाल में हालात इस कदर हद तक बिगड़ बिगड़ने की करें तो, तीनों बड़ी पार्टियों,नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी और माओवादी सेंटर के नेताओं के घरों मेंघुसकर लोगों ने मारपीट की, घरों को आग के हवाले कर दिया और वित्तमंत्री को सड़कों पर घसीटा गया। एक पूर्व प्रधानमंत्री के घर में आगजनी के दौरान उनकी पत्नी की मौत हुई तो उधर जनाक्रोश [illegible] दिया। यह दृश्य केवल राजनीतिक विद्रोह का नहीं बल्कि व्यवस्था के खिलाफ पूर्ण असंतोष का प्रतीक है। युवाओं का यह क्रोध इस बात का संकेत है कि अब पारंपरिक राजनीति को बदलने का समय आ चुका है। साथियों बात अगर हम नेपाल की स्थिति की तुलना श्रीलंका और बांग्लादेश से करने की करें तो,यहाँ हाल के वर्षों में आर्थिक संकट और राजनीतिकअस्थिरता ने जनता को सड़कों पर ला दिया था। श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन तक जनता का कब्जा, बांग्लादेश में चुनावी धांधली के खिलाफ आंदोलन और म्यांमार में सैन्य तख्तापलट ने दक्षिण एशिया की राजनीति को लगातार अस्थिर बना रखा है। अब नेपाल भी उसी राह पर चलते हुए सत्ता पलट की कगार पर पहुंच गया है। इसका सीधा संकेत है कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद से जूझ रहे समाजों में युवा अब चुप बिल्कुल नहीं बैठेंगे। साथियों बात अगर हम नेपाल के इस पूरे घटनाक्रम में सोशल मीडिया की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होने की करें तो, नेपाल की लगभग 87 प्रतिशत आबादी मोबाइल इंटरनेट का उपयोग करती है, जबकि 62 प्रतिशत लोग सक्रिय रूप से फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। ट्विटर और यूट्यूब पर भी युवा लगातार अपने विचार साझा कर रहे हैं। नेताओं के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया पर अपने आलीशान जीवन और लग्ज़री छुट्टियों की तस्वीरें पोस्ट करना आग में घी का काम साबित हुआ। जब देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से जूझ रही हो और नेता तथा उनके परिवार ऐशो- आराम की तस्वीरें साझा करें, तो यह जनता के लिए असहनीय हो जाता है। यही वजह है कि सोशल मीडिया ने जनाक्रोश को संगठित आंदोलन में बदल दिया। साथियों बात अगर हम भारत के पड़ोस में यहराजनीतिक उथल- पुथल चिंता का विषय होने की करें तो,नेपाल बांग्लादेश,श्रीलंका म्यांमार और पाकिस्तान सभी वर्तमान में या तो राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहे है या सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया में है। म्यांमार में सेना का शासन है, पाकिस्तान में सरकार और सेना के बीच टकराव है, श्रीलंका अब भी आर्थिक संकट से जूझ रहा है, और बांग्लादेश में युवाओं के विद्रोह ने लोकतंत्र को झकझोर दिया है।

इन सबके बीच नेपाल का यह आंदोलन दक्षिण एशिया में एक नई लहर पैदा कर सकता है।इतिहास की दृष्टि से देखें तो श्रीलंका,पाकिस्तान और म्यांमार कभी अखंड भारत का हिस्सा रहे थे। आज ये दक्षिण एशिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है और सभी देशों में एक जैसी राजनीतिक चुनौतियाँ दिखाई दे रही है, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, परिवारवाद, लोकतांत्रिक संस्थाओं की कमजोरी और युवा असंतोष। यही वजह है कि नेपाल की घटनाएँ केवल एक देश की समस्या नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की राजनीति के लिए चेतावनी है। साथियों बात अगर हम नेपाल के घटनाक्रम नेपाल में सत्ता पलट का भारत पर सीधा प्रभाव पड़ना स्वाभाविक होने की करें तो,भारत और नेपाल के बीच गहरे सांस्कृतिक, आर्थिक और भौगोलिक संबंध है। दोनों देशों की खुली सीमा, व्यापार, पानी और ऊर्जा परियोजनाएँ भारत को नेपाल के साथ मजबूती से जोड़ती है।यदि नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है तो इसका असर भारत की सुरक्षा, सीमावर्ती क्षेत्रों की शांति और आर्थिक हितों पर अवश्य पड़ेगा। चीन और पाकिस्तान जैसे देश नेपाल में बढ़ती अस्थिरता का फायदा उठाकर भारत विरोधी गतिविधियों को प्रोत्साहित कर सकते है। इसलिए भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह नेपाल की स्थिरता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का समर्थन दे। साथियों बात अगर हम युवाओं की जागरूकता की करें तो नेपाल का यह विद्रोह यह भी दर्शाता है कि दक्षिण एशिया के युवाओं में अब जागरूकता का स्तर काफी बढ़ चुका है। वे केवल भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन तक सीमित नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए आगे आ रहे है। नेपो बेबीज और पारिवारिक राजनीति के खिलाफ उठी यह आवाज अब केवल नेपाल तक सीमित नहीं रहेगी,बल्कि बांग्लादेश,श्रीलंका, पाकिस्तान और यहाँ तक कि भारत में भी राजनीतिक वंशवाद के खिलाफ नई बहस को जन्म देगी।आगे चलकर नेपाल के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि यह जनआंदोलन केवल सत्ता पलट तक सीमित न रह जाए, बल्कि एक स्थायी और पारदर्शी व्यवस्था में बदल सके। यदि यह आंदोलन केवल भावनाओं के आधार पर चला और संस्थागत सुधारों तक नहीं पहुँचा, तो नेपाल बार-बार उसी राजनीतिक अस्थिरता का शिकार होगा जो पिछले तीन दशकों से जारी है। लेकिन यदि युवा इस ऊर्जा को सही दिशा देते है, तो नेपाल न केवल खुद को बदल सकता है बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए प्रेरणा बन सकता है। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि नेपाल में युवाओं का आक्रोश, सत्ता पलट और दक्षिण एशिया की राजनीति-एक अंतरराष्ट्रीय विश्लेषणविश्व में युवा पीढ़ी ही अपने देश की राजनीति का भविष्य तय करने वाली है नेपाल में भ्रष्टाचार व परिवारवाद के खिलाफ़ युवाओं के जबरदस्त आक्रोश को दुनियाँ के हर देश को संज्ञान में लेना जरूरी है।

सम्पादकीय...

पंजाब की तबाही किसी प्रलय से कम नहीं

घुटनेभर पानी में तस्वीर खिंचवाने के बाद केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब की स्थिति को जलप्रलय कहा है और साथ ही भरोसा भी दिलवाया कि केन्द की सरकार 'पंजाब के साथ मजबूती से खड़ी है'। शिवराज सिंह चौहान की बात सही है। पंजाब की तबाही किसी प्रलय से कम नहीं है। ऐसी भयंकर बाढ़ इससे पहले 1988 में आई थी जब 500 लोग मारे गए थे पर विशेषज्ञ बता रहे है कि आज स्थिति 1988 से भी अधिक नाजुक और संकटपूर्ण है। उस वक्त 12 जिले प्रभावित हुए थे जबकि इस बार सभी 23 जिले बाढ़ की गिरफ्त में है। अनुमान है कि 4 लाख एकड़ खेत पानी से भर गए है। 2000 गांव पानी में डूब चुके है। 4 लाख लोग प्रभावित हुए है जो 1988 से लगभग 3 लाख ज्यादा है। सीमा पर तैनात एक बीएसएफ अधिकारी ने बताया है कि पानी की भारी मात्रा ने देहात की तस्वीर ही बदल दी है। सवाल है कि क्या कुछ बचाव हो सकता था? पहली बात तो है कि जितनी बारिश और जिस वेग के साथ हुई है वह पहले नहीं देखी गई। बीबीएमबी के चेयरमैन के अनुसार पौंग डैम में इतना पानी कभी नहीं आया। पंजाब के तीनों बड़े डैम, भाखड़ा,पौंग और रणजीत सागर लबालब भरे हुए हैं। इस बार डैमों में 20-25फीसदी पानी अधिक आया है। जब इतनी बारिश हो तो सरकार भी बेबस हो जाती है पर हिमाचल प्रदेश से लेकर पंजाब तक इस बार जो तबाही हुई है वह केवल कुदरत की मार ही नहीं है। जैसे मैंने तीन सप्ताह पहले भी लिखा था, जो हुआ है वह इंसानी बेवकूफी का भी परिणाम है पर अब पता चलता है कि यह मामला केवल बेवकूफी का ही नहीं, यह सरकारी उदासीनता और लापरवाही का भी है। बार-बार होती तबाही के बावजूद सरकारें सोई रहती हैं और तब जागती है जब पानी सर तक पहुंच चुका होता है। असंख्य सर्वेक्षण और अध्ययन बता चुके है कि तबाही के पीछे न केवल 'ह्यूमन फैक्टर' है बल्कि 'गवर्नेन्स फैक्टर' भी है। बारिश की पहली मार हिमाचल प्रदेश को झेलनी पड़ती है। इस बार जितनी तबाही हुई कि पहले नहीं हुई। 900 सड़कें ब्लॉक है। कुछ बह गई तो कुछ को भूस्खलन ने रोक दिया है। बहुत पुल टूट चुके है। 1500 पॉवर ट्रांसफार्मर बंद पड़े है। 400 पीने के पानी की स्कीमें काम नहीं कर रहीं। सरकार के अनुसार 4000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है जो यह प्रदेश झेल ही नहीं सकता। 366 लोग मारे गए है। सड़कें तो लाइफ लाइन है। न टूरिस्ट आ रहा है और न ही सेब बाहर जा रहा है। पर क्या यह केवल कुदरत की मार ही थी या प्रदेश ने ही अपनी तबाही का इंतजाम कर लिया था? बाढ़ में पौंग डैम और चम्बा के पास बहकर आई लकड़ियों के वीडियो देखकर चिन्तित सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार और सम्बंधित संस्थाओं को नोटिस जारी किया है कि 'पेड़ों के अवैध कटान ने इस आपदा को आमंत्रित किया है'। हिमाचल प्रदेश का वन विभाग अवैध कटान से इंकार करता है पर यह तो खुला रहस्य है कि हमारे पहाड़ी प्रदेशों में ज़ोर-शोर से अवैध कटान होता है। वन कटाई बाढ़ और भूस्खलन को आमंत्रित करती है। आशा है कि सुप्रीम कोर्ट मामले को अंत तक लेकर जाएगा, क्योंकि हिमाचल सरकार में रोकने का दम नहीं है। मुख्यमंत्री ने कोई सीआईडी की जांच बैठा कर मामला दाखिल दफ्तर कर दिया है। तेज शहरीकरण हिमाचल के लिए खतरा बन रहा है। सरकार अवैध निर्माण के आगे हथियार फेंक कर बैठ गई, जिसका एक परिणाम हम मनाली में देख रहे है जहां ब्यास नदी बहुत बड़ा हिस्सा बहा कर ले गई है। एक संसदीय कमेटी ने हाईवे निर्माण पर सवाल उठाए है कि ऊंची सड़कें पानी के प्राकृतिक बहाव में रुकावट डाल रहे हैं। बेधड़क हाईवे निर्माण से पहाड़ खिसकने लगे हैं, जैसा मैंने पहले लेख में भी लिखा था, पर क्या हिमाचल की सरकार ने यह मामला एनएचएआई से उठाया है? जहां तक पंजाब का सवाल है, जो केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है उससे तो लगता है कि इतनी बड़ी तबाही का बड़ा कारण प्रशासनिक उदासीनता और निठुराई है। मंत्री का आरोप है कि दरिया के किनारे बने बांध अवैध खनन से कमजोर हो गए और पानी गांवों में घुस गया। उन्होंने बताया कि वाजपेयी और प्रकाश सिंह बादल की सरकारों के समय सतलुज, ब्यास, रावी और घग्गर के किनारों पर बने धुस्सी बांधों को मजबूत और ऊंचा किया गया था, पर अब यह कमजोर पड़ गए है और पानी की मार नहीं सह सकें। पर अवैध खनन केवल बांधों पर ही नहीं हो रहा। नदी तट पर भी लगातार अवैध खनन चलता है जो नदी के तट को छिछला कर देता है और ऐसा सबको आंखों के सामने हो रहा है पर कोई रोक नहीं है। बाढ़ का पानी तो पहाड़ों से आता है, जो सही बात पंजाब के मंत्री दोहरा रहे है, पर क्या हम इसे सम्भालने के लिए तैयार भी थे? हर दो तीन वर्ष के बाद पंजाब में बाढ़ आ रही है पर हम बेतैयार क्यों पाए जाते है? अवैध खनन और अव्यवस्थित निर्माण के कारण ड्रेनेज सिस्टम कमजोर पड़ गया जो जल प्रवाह को रोक नहीं सका। गुड़गांव और बैंगलुरू जैसे शहरों में भी निकासी के ऊपर निर्माण ने हमारे हाई-टैक शहरों को पानी में डुबो दिया था। बहुत विशेषज्ञ कई सालों से चेतावनी दे रहे हैं कि ड्रेन और नहरों की सफाई न होने के कारण पानी की प्राकृतिक निकासी रुक जाती है। इसके अलावा धुस्सी बांधों की कमजोर हालत, [illegible] की कमी और नदी किनारे बिना सोचे-समझे निर्माण के कारण स्थिति और विकराल हो गई है। समय के साथ नदियों की पानी ले जाने की क्षमता कम हुई है। नदियों में गाद जम गई है। नदी और नालों की सफाई और उन पर से अतिक्रमण को हटाने की तत्काल जरूरत है पर इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। बारिश कुछ रुकी है पर अभी त्रासदी का अंत नहीं हुआ। पंजाब में लाखों बेघर है। धान की फसल बर्बाद हो चुकी है। पशु बह गए हैं। मकान गिर गए हैं। बाढ़ अपने पीछे भारी विनाश छोड़ गई है। लोग अंधकारमय भविष्य की तरफ देख रहे हैं। पंजाब की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है। बाज़ारों में रौनक नहीं है। एक बार पानी उतर गया तो मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां फैलना शुरू हो जाएगी। बहुत लोग अभी से डायरिया, त्वचा की बीमारियों और उल्टी दस्त के कारण अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। पंजाब में ऐसी बाढ़ से देश की खाद्यान्न सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि अन्न भंडार में पंजाब सबसे अधिक योगदान डालता है।

भविष्य की राजनीति तय करेगा बिहार चुनाव

बिहार में होने वाला चुनाव सिर्फ एक लोकतांत्रिक कवायद नहीं है, इसमें तीन दिग्गजों -नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की राजनीति दांव पर लगी है। दो दल-जदयू और लोजपा अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे है, जबकि शक्तिशाली भाजपा और इंडिया का भंगुर गठबंधन सबसे कठिन लड़ाई में जूझने जा रहे है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पांच बार चुनाव जीता है, परंतु यह उनका निर्णायक चुनाव होगा। उनकी पार्टी का वोट प्रतिशत 2010 के 22.6 फीसदी से घटकर 2020 में 15.7 प्रतिशत रह गया। ढांचागत सुधार, विद्युतीकरण में वृद्धि तथा कानून-व्यवस्था की स्थिति बेहतर करने जैसी उनकी उपलब्धियां निर्विवाद है, लेकिन अब उन पर थकान भारी पड़ रही है। बेरोजगारी बिहार की आत्मा से जुड़ी है, और 75 लाख लोग बिहार से बाहर मेहनत कर जीविका चला रहे है। विस्थापन एक ऐसा घाव है, जो भरना ही नहीं चाहता। नीतीश कुमार को अपने दम पर बहुमत लाना होगा, ताकि एनडीए में अपनी पार्टी की प्रासंगिकता बनाये रखें, जिसने उन्हें मुख्यमंत्री प्रस्तावित किया है। इससे कुछ स्थानीय भाजपा नेता परेशान है, जो बड़ी भूमिका चाहते है। बिहार की राजनीति में बड़ी भूमिका इन दिनों तेजस्वी यादव निभा रहे है। इस चुनाव में उन्हें लालू के बेटे से अलग पहचान साबित करनी होगी। इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रहे तेजस्वी अपने मुस्लिम-यादव जनाधार पर निर्भर है, जिसके बूते 2020 के चुनाव में 75 सीटें जीत राजद राज्य का सबसे बड़ा दल बनकर उभरा है। एनडीए के मजबूत जातिगत समीकरण को चुनौती देने के लिए तेजस्वी को अब ओबीसी, दलितों और कमजोर तबकों तक पहुंच बनानी होगी। तेजस्वी के तेज, युवा केंद्रित और तकनीकी दक्षता से लैस चुनाव अभियान का दायरा बढ़ रहा है। एक ओपिनियन पोल के मुताबिक, मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी 36.9 प्रतिशत रेटिंग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 18.4 फीसदी रेटिंग से बहुत आगे है। इसके बावजूद तेजस्वी पर लालू यादव के दौर के जंगल राज का ठप्पा लगा हुआ है, लालटेन चुनाव चिह्न के आधार पर विपक्ष राजद को प्रगति विरोधी भी कहता है। बिहार के रण में राहुल गांधी भी अपनी योग्यता साबित करना चाहते है। वर्ष 2020 में 19 सीटें जीतने वाली कांग्रेस गठबंधन में जूनियर पार्टनर है, फिर भी चुनाव में कांग्रेस की भूमिका बड़ी है। यह चुनाव न केवल इस प्रांत में कांग्रेस की संभावनाओं की परीक्षा है, इसमें कांग्रेस का प्रदर्शन इंडिया गठबंधन के संभावित प्रधानमंत्री के रूप में राहुल की नियति भी तय करेगा। तेजस्वी और कन्हैया कुमार के साथ राज्य पदयात्रा में उन्होंने उन मुद्दों को उभारा, जो युवाओं के मुद्दे है। यानी बेरोजगारी, विस्थापन और आर्थिक महत्वाकांक्षा। ऐसे ही, प्रियंका के साथ राहुल की साझा रैलियों का उद्देश्य कभी कांग्रेस के गढ़ रहे इलाकों में पार्टी को फिर से मजबूत बनाना था। राहुल गांधी के 'वोट चोरी' तथा चुनाव आयोग के पक्षपात के आरोप सार्वजनिक झगड़े में बदल गये है, जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने सावधानी से जांच करने को कहा है। कांग्रेस के 'पलायन रोको, नौकरी दो' का नारा बिहार की हकीकत से जुड़ गया है, जहां के 51.2 फीसदी मतदाताओं ने रोजगार को अपनी प्रमुख प्राथमिकता बतायी है। नेहरू के वैज्ञानिक समाजवाद के नजरिये को मौजूदा समय संदर्भ में ढालकर राहुल गांधी कांग्रेस की परंपरागत धर्मनिरपेक्ष सोच को समसामयिक आर्थिक लोक- प्रियतावाद से जोड़ते दिखाई देते है।

भाजपा के एजेंडे में आदर्शवाद कहीं नहीं है। एनडीए की चुनावी गाड़ी बिहार में एक असामान्य बाधा का सामना कर रही है, राज्य में एक भी करिश्माई स्थानीय नेता नहीं है। ऐसे में, भाजपा नरेंद्र मोदी की व्यापक लोकप्रियता व चुंबकीय व्यक्तित्व तथा अमित शाह के रणनीतिक कौशल के सहारे आगे बढ़ेगी। वर्ष 2020 के 74 सीटों से आगे बढ़ने के लिए पार्टी मोदी के विकासवादी विमर्श के साथ राजद के दौर में कानून-व्यवस्था की विफलता को याद दिलायेगी। चुनाव विश्लेषक एनडीए के पक्ष में 48.9 प्रतिशत तथा इंडिया गठबंधन के पक्ष में 35.8 फीसदी समर्थन का आंकड़ा दे रहे है। परंतु एनडीए सहयोगियों में सब कुछ ठीक नहीं दिखता। सीटों के मामले में चिराग पासवान की लोजपा और जदयू के बीच मतभेद है। चिराग पासवान 20-25 सीटें मांग रहे है, पर जदयू इतनी सीटें देना नहीं चाहता. चिराग पासवान बिहार चुनाव में सबसे अप्रत्याशित चेहरे के रूप में सामने है। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में पांच सीटों पर शानदार जीत बिहार में पासवान मतदाताओं के बीच, जिनकी आबादी राज्य में अच्छी-खासी है, चिराग की लोकप्रियता का सबूत था। अगर चुनाव में भाजपा और जदयू में से किसी को निर्णायक बहुमत नहीं मिलता, तो मुख्यमंत्री के चयन में चिराग की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। उनके द्वारा नीतीश कुमार के राज में कानून-व्यवस्था की आलोचना एनडीए में अंदरूनी दरार के बारे में बताती है। एनडीए के मजबूत जातिगत समीकरण को मोदी की रैलियों ने मजबूती प्रदान की है, जिसमें कल्याणकारी योजनाओं तथा ढांचागत सुधारों के बारे में बताया जाता है। एआई की मदद से बनाये गये मीम्स तथा प्रभावी संदेशों से भरपूर राजद का डिजिटल अभियान एनडीए के व्हाट्सएप संदेशों तथा डोर-टू-डोर कैंपेन से बिल्कुल अलग है। बिहार की राजनीति अब भी जातिगत समीकरणों पर निर्भर है। एक सर्वे बताता है, 51.2 फीसदी मतदाताओं ने बेरोजगारी को, 45.7 प्रतिशत वोटरों ने मुद्रास्फीति को और 41 फीसदी वोटरों ने भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बताया है.

पर जातिगत समीकरणों को, नीतीश द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों तथा चिराग द्वारा पासवान मतदाताओं, साधने के कौशल के कारण एनडीए अपने प्रतिद्वंद्वी पर भारी है। दूसरी ओर, मुस्लिम, यादव, बहुजन, आदिवासी और गरीब मतदाताओं के अपने जनाधार को राजद और व्यापक करने की कोशिश में है। सभी 243 सीटों पर लड़ रही जन सुराज पार्टी जातिगत समीकरणों को महत्व नहीं दे रही। पर इसके नेता प्रशांत किशोर की मुख्यमंत्री के रूप में रेटिंग मात्र 16.4 फीसदी है। बेशक विस्थापन पर केंद्रित कांग्रेस का अभियान जोर पकड़ रहा है, पर इंडिया गठबंधन में अंदरूनी खींचातानी इसे बाधित कर सकती है। बिहार का चुनाव एनडीए और इंडिया गठबंधन, दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। राज्य के मतदाता सिर्फ अगले मुख्यमंत्री का ही चयन नहीं करेंगे, वे भारत के राजनीतिक भविष्य की भी नींव रखेंगे।

नेपाल में जेन जेड विद्रोह

नेपाल की जेन-जैड विद्रोह के बाद ओली सरकार का तख्ता पलटने पर रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां याद आती है। जब किसी भी देश की जनता आक्रोशित और आंदोलित हो जाए तो सब कुछ खाक हो जाता है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देकर भागना पड़ा। क्रुद्ध लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री झाला नाथ खनाल की पत्नी को जिन्दा जला दिया। वित्त मंत्री और अन्य मंत्रियों को सड़कों पर पीटा। सत्ता का केन्द्र बिन्दु रहे सिंह दरबार, संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास और अन्य ऐतिहासिक इमारतें धू-धू कर जलीं। पहली नजर में युवाओं का विद्रोह सोशल मीडिया पर लगाई गई पाबंदियों के विरोध में नजर आया लेकिन बाद में यह? विरोध हिंसक संघर्ष में तब्दील हो गया। हिंसा में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए है। अब सवाल यह है कि नेपाल आखिर क्यों उबला? पड़ोसी देश में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि घर में एक पीढ़ी विद्रोह कर दे जबकि हर महीने हजारों लोग नौकरी करने के? लिए विदेश भाग रहे है। स्पष्ट है कि हिंसा और अशांति की जड़ें बहुत गहरी है। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस में भ्रष्टाचार के ?विरोध में प्रदर्शन हुए तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह नेपाल तक फैल जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रतिबंध लगाया जाना युवाओं के आक्रोश के? लिए ट्रिगर साबित हुआ। केपी?शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार ने भी बरबरता की पराकाष्ठा की, जब पुलिस फायरिंग से स्कूली बच्चों समेत 20 लोग मारे गए। जेन ज़ेड के नेतृत्व वाले प्रदर्शनों को नेपाल में हाल ही में हुई घटनाओं की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। यह सिर्फ सोशल मीडिया पर प्रतिबंध का विरोध नहीं है। इंडोनेशिया और फिलीपींस की तरह, नेपाली सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने भी टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके सांसदों और राजनेताओं के बच्चों और रिश्तेदारों की विलासितापूर्ण जीवनशैली और यात्राओं के लिए सार्वजनिक रूप से आलोचना की, जबकि देश का अधिकांश हिस्सा गरीबी और कठिनाइयों से जूझ रहा था। कई हाई-प्रोफाइल भ्रष्टाचार घोटालों का प्रचार करते हुए, उन्होंने उल्लेख किया कि करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल नेपो बेबीज की जीवनशैली को वित्तपोषित करने के लिए किया जा रहा है। हिंसा के पीछे संस्थागत भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत और राजनीतिक असंतोष की बड़ी भूमिका है। पिछले 4 वर्षों में नेपाल में कई बड़े घोटाले सामने आए, जिसमें गिरि बंधु भूमि, स्वैप घोटाला जो 54,600 करोड़ का बताया जाता है। 13000 करोड़ का ओरिएंटल कॉरपोरेटिव घोटाला और लगभग 70 हजार करोड़ का कॉरपोरेटिव घोटाला शामिल है। इन बड़े घोटालों में आम जनता का विश्वास सरकार से पूरी तरह से उठ चुका है। नेपाल में 10.71 प्रतिशत युवा बेरोजगार है। जबकि महंगाई आसमान को छू रही है। देश की कुल सम्पत्ति का 56 प्रतिशत हिस्सा केवल 20 प्रतिशत लोगों के पास है, जिनमें अधिकतर राजनीतिज्ञ शामिल है। अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता है।

मोहन भागवत जी हमेशा से 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' के प्रबल समर्थक रहे हैं

11 सितंबर है। यह दिन अलग-अलग स्मृतियों से जुड़ा है। एक स्मृति 1893 की है, जब स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्वबंधुत्व का संदेश दिया और दूसरी स्मृति है 9/11 का आतंकी हमला, जब विश्व बंधुत्व को सबसे बड़ी चोट पहुंचाई गई। आज के दिन की एक और विशेष बात है। आज एक ऐसे व्यक्तित्व का 75वां जन्मदिवस है जिन्होंने वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र पर चलते हुए समाज को संगठित करने, समता-समरसता और बंधुत्व की भावना को सशक्त करने में अपना पूरा जीवन समर्पित किया है।संघ परिवार में जिन्हें परम पूजनीय सरसंघचालक के रूप में श्रद्धाभाव से संबोधित किया जाता है, ऐसे आदरणीय मोहन भागवत जी का आज जन्मदिन है। यह एक सुखद संयोग है कि इसी साल संघ भी अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। मैं भागवत जी को हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उन्हें दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। मेरा मोहन भागवत जी के परिवार से बहुत गहरा संबंध रहा है। मुझे उनके पिता, स्वर्गीय मधुकरराव भागवत जी के साथ निकटता से काम करने का सौभाग्य मिला था। मैंने अपनी पुस्तक ज्योतिपुंज में मधुकरराव जी के बारे में विस्तार से लिखा भी है। वकालत के साथ-साथ मधुकरराव जी जीवनभर राष्ट्र निर्माण के कार्य में समर्पित रहे। अपनी युवावस्था में उन्होंने लंबा समय गुजरात में बिताया और संघ कार्य की मजबूत नींव रखी। मधुकरराव जी का राष्ट्र निर्माण के प्रति झुकाव इतना प्रबल था कि अपने पुत्र मोहनराव को भी इस महान कार्य के लिए निरंतर गढ़ते रहे। एक पारसमणि मधुकरराव ने मोहनराव के रूप में एक और पारसमणि तैयार कर दी। भागवत जी का पूरा जीवन सतत प्रेरणा देने वाला रहा है। वे 1970 के दशक के मध्य में प्रचारक बने। सामान्य जीवन में प्रचारक शब्द सुनकर ये भ्रम हो जाता है कि कोई प्रचार करने वाला व्यक्ति होगा, लेकिन जो संघ को जानते है उनको पता है कि प्रचारक परंपरा संघ कार्य की विशेषता है। गत 100 वर्षों में देशभक्ति की प्रेरणा से भरे हजारों युवक-युवतियों ने अपना घर-परिवार त्याग करके पूरा जीवन संघ परिवार के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया है। भागवत जी भी उस महान परंपरा की मजबूत धुरी है। भागवत जी ने उस समय प्रचारक का दायित्व संभाला, जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने देश पर इमरजेंसी थोप दी थी। उस दौर में प्रचारक के रूप में भागवत जी ने आपातकाल-विरोधी आंदोलन को निरंतर मजबूती दी। उन्होंने कई वर्षों तक महाराष्ट्र के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों, विशेषकर विदर्भ में काम किया। 1990 के दशक में अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख के रूप में मोहन भागवत जी के कार्यों को आज भी कई स्वयंसेवक स्नेहपूर्वक याद करते है। इसी कालखंड में मोहन भागवत जी ने बिहार के गांवों में अपने जीवन के अमूल्य वर्ष बिताए और समाज को सशक्त करने के कार्य में समर्पित रहे। वर्ष 2000 में वे सरकार्यवाह बने और यहाँ भी भागवत जी ने अपनी अनोखी कार्यशैली से हर कठिन परिस्थिति को सहजता और सटीकता से संभाला। 2009 में वे सरसंघचालक बने और आज भी अत्यंत ऊर्जा के साथ कार्य कर रहे है। भागवत जी ने राष्ट्र प्रथम की मूल विचारधारा को हमेशा सर्वोपरि रखा। सरसंघचालक होना मात्र एक संगठनात्मक जिम्मेदारी नहीं है। यह एक पवित्र विश्वास है, जिसे पीढ़ी-दर-पीढ़ी दूरदर्शी व्यक्तित्वों ने आगे बढ़ाया है और इस राष्ट्र के नैतिक और सांस्कृतिक पथ को दिशा दी है। असाधारण व्यक्तियों ने इस भूमिका को व्यक्तिगत त्याग, उद्देश्य की स्पष्टता और माँ भारती के प्रति अटूट समर्पण के साथ निभाया है। यह गर्व की बात है कि मोहन भागवत जी ने न केवल इस विशाल जिम्मेदारी के साथ पूर्ण न्याय किया है, बल्कि इसमें अपनी व्यक्तिगत शक्ति, बौद्धिक गहराई और सहृदय नेतृत्व भी जोड़ा है। भागवत जी का युवाओं से सहज जुड़ाव है और इसलिए उन्होंने अधिक से अधिक युवाओं को संघ कार्य के लिए प्रेरित किया है। वे लोगों से प्रत्यक्ष संपर्क में रहते है, और संवाद करते रहते है। श्रेष्ठ कार्य पद्धति को अपनाने की इच्छा और बदलते समय के प्रति खुला मन रखना, ये मोहनजी की बहुत बड़ी विशेषता रही है। अगर हम व्यापक संदर्भ में देखते हैं तो संघ की 100 साल की यात्रा में भागवत जी का कार्यकाल संघ में सर्वाधिक परिवर्तन का कालखंड माना जाएगा। चाहे वो गणवेश परिवर्तन हो, संघ शिक्षा वर्गों में बदलाव हो, ऐसे अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन उनके निर्देशन में संपन्न हुए। कोरोना काल में मोहन भागवत जी के प्रयास विशेष रूप से याद आते है। उस कठिन समय में उन्होंने स्वयंसेवकों को सुरक्षित रहते हुए समाजसेवा करने की दिशा दी और टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाने पर बल दिया। उनके मार्गदर्शन में स्वयंसेवकों ने जरूरतमंदों तक हरसंभव सहायता पहुँचाई, जगह-जगह मेडिकल कैंप लगाए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों और वैश्विक विचार को प्राथमिकता देते हुए व्यवस्थाओं को विकसित किया। हमें कई स्वयंसेवकों को खोना भी पड़ा, लेकिन भागवत जी की प्रेरणा ऐसी थी कि अन्य स्वयंसेवकों की दृढ़ इच्छाशक्ति कमजोर नहीं पड़ी। इस वर्ष की शुरुआत में, मैंने नागपुर में उनके साथ माधव नेत्र चिकित्सालय के उद्घाटन के दौरान मैंने कहा था कि संघ अक्षयवट की तरह है, जो राष्ट्रीय संस्कृति और चेतना को ऊर्जा देता है। इस अक्षयवट वृक्ष की जड़ें इसके मूल्यों की वजह से बहुत गहरी और मजबूत है। इन मूल्यों को आगे बढ़ाने में जिस समर्पण से मोहन भागवत जी जुटे हुए हैं, वो हर किसी को प्रेरणा देता है। समाज कल्याण के लिए संघ की शक्ति के निरंतर उपयोग पर मोहन भागवत जी का विशेष बल रहा है। इसके लिए उन्होंने पंच परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया है। इसमें स्व बोध, सामाजिक समरसता, नागरिक शिष्टाचार, कुटुम्ब प्रबोधन और पर्यावरण के सूत्रों पर चलते हुए राष्ट्र निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। देश और समाज के लिए सोचने वाले हर भारतवासी को पंच परिवर्तन के इन सूत्रों से अवश्य प्रेरणा मिलेगी। संघ का हर कार्यकर्ता वैभव संपन्न भारत माता का सपना साकार होते देखना चाहता है। इस सपने को पूरा करने के लिए जिस स्पष्ट विज़न और ठोस एक्शन की जरूरत होती है, मोहन जी इन दोनों गुणों से परिपूर्ण है। मोहन जी के स्वभाव की एक और बड़ी विशेषता ये है कि वो मृदुभाषी है। उनमें सुनने की भी अद्भुत क्षमता है। यह विशेषता न केवल उनके दृष्टिकोण को गहराई देती है, बल्कि उनके व्यक्तित्व और नेतृत्व में संवेदनशीलता और गरिमा भी लाती है। मोहन जी, हमेशा 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के प्रबल पक्षधर रहे हैं। भारत की विविधता और भारत भूमि की शोभा बढ़ा रही अनेक संस्कृतियों और परंपराओं के उत्सव में भागवत जी पूरे उत्साह से शामिल होते है। वैसे बहुत कम लोगों को ये पता है कि मोहन भागवत जी अपनी व्यस्तता के बीच संगीत और गायन में भी रुचि रखते है। वे विभिन्न भारतीय वाद्ययंत्रों में भी निपुण है। पठन-पाठन में उनकी रुचि, उनके अनेक भाषणों और संवादों में साफ दिखाई देती है। पिछले दिनों देश में जितने सफल जन-आंदोलन हुए, चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोहन भागवत जी ने पूरे संघ परिवार को इन आंदोलनों में ऊर्जा भरने के लिए प्रेरित किया। मैं पर्यावरण से जुड़े प्रयासों और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को आगे बढ़ाने के प्रति उनके समर्पण को जानता हूँ। मोहन जी का बहुत जोर आत्मनिर्भर भारत पर भी है। कुछ ही दिनों में विजयादशमी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष का हो जाएगा। यह भी सुखद संयोग है कि विजयादशमी का पर्व, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती और संघ का शताब्दी वर्ष एक ही दिन आ रहे है यह भारत और विश्वभर के लाखों स्वयंसेवकों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। हम स्वयंसेवकों का सौभाग्य है कि हमारे पास मोहन भागवत जी जैसे दूरदर्शी और परिश्रमी सरसंघचालक है, जो ऐसे समय में संगठन का नेतृत्व कर रहे है। एक युवा स्वयंसेवक से लेकर सरसंघचालक तक की उनकी जीवन यात्रा उनकी निष्ठा और वैचारिक दृढ़ता को दर्शाती है। विचार के प्रति पूर्ण समर्पण और व्यवस्थाओं में समयानुकूल परिवर्तन करते हुए उनके नेतृत्व में संघ कार्य का निरंतर विस्तार हो रहा है। मैं माँ भारती की सेवा में समर्पित मोहन भागवत जी के दीर्घ और स्वस्थ जीवन की पुनः कामना करता हूँ।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वन्दना ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, सराय पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2019/[illegible])

जीएसटी कटौती दोपहिया ग्राहकों के लिए कार खरीदने का अवसरः मारुति

नई दिल्ली ।

देश की प्रमुख कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) को उम्मीद है कि वाहनों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों में कटौती के बाद अगले वित्त वर्ष से घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वृद्धि लगभग सात प्रतिशत पर वापस आ जाएगी। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह बात कही। मारुति सुजुकी इंडिया के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी (विपणन एवं बिक्री) पार्थो बनर्जी ने सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) के वार्षिक सम्मेलन के मौके पर संवाददाताओं से कहा कि छोटी कार खंड, जिसमें कंपनी का दबदबा है, में वृद्धि की उम्मीद लगभग 10 प्रतिशत है। जीएसटी दर में कमी के वाहन बिक्री वृद्धि पर प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ''भारतीय वाहन उद्योग के लिए दीर्घकालिक विकास चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) जो पहले लगभग सात प्रतिशत हुआ करती थी, हमें लगता है कि 2026-27 से यह फिर से उसी स्तर पर आ जाएगी। छोटी कारों के लिए, उन्होंने कहा, ''हमें उम्मीद है कि यह 10 प्रतिशत रहेगी। उन्होंने कहा कि 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर आयकर में छूट, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में कटौती से मासिक किस्त (ईएमआई) कम होगी, और जीएसटी दर में कमी जैसे कई कारक छोटी कारों को और अधिक किफायती बनाने में मदद करेंगे जिससे दोपहिया वाहन चालकों को कार खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा, ''हमारा मानना है कि यह सभी दोपहिया वाहन ग्राहकों के लिए चार पहिया वाहन में 'अपग्रेड करने का एक बड़ा अवसर है। पिछले कुछ वर्षों में, विशेष रूप से छोटी कार श्रेणी में, सामर्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण, घरेलू यात्री वाहन (पीवी) की बिक्री धीमी रही है।

उद्योग के अनुमानों के अनुसार, इस वित्त वर्ष की अप्रैल-अगस्त अवधि में, यात्री वाहनों की बिक्री लगभग 17.05 लाख इकाई रही, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 17.31 लाख इकाई थी। बनर्जी ने कहा कि जीएसटी दर में कमी के बाद चालू वित्त वर्ष के उत्तरार्ध में बिक्री में तेजी आने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि जीएसटी दरों में कटौती की घोषणा के बाद से, 'श्राद्ध का समय होने के बावजूद पूछताछ में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और बाजार का रुझान उत्साहजनक है। बनर्जी ने यह भी कहा कि कंपनी ने जीएसटी दरों में कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने की घोषणा पहले ही कर दी है।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का पहला चरण नवंबर तक होगा पूरा, पीयूष गोयल ने दिए संकेत

नई दिल्ली । केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संकेत दिया कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के पहला चरण को नवंबर तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा। पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने मिलकर हमें निर्देश दिया था कि दोनों पक्षों के मंत्री नवंबर 2025 तक एक अच्छा समझौता कर लें। उस समझौते का पहला भाग नवंबर 2025 तक अंतिम रूप दे दी जाए और मार्च से ही इस विषय पर बहुत अच्छे माहौल में बहुत गंभीरता से चर्चा चल रही है और इस प्रगति से दोनों पक्ष संतुष्ट हैं। इससे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में संकेत दिया था कि भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर कुछ नरमी आई है, उन्होंने कहा था कि दोनों देश व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं। उन्होंने पोस्ट किया कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका अपने दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं। मैं आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त, प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ट्रम्प की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब कुछ दिन पहले ही उन्होंने भारत-अमेरिका संबंधों को बहुत विशेष संबंध बताया था और कहा था कि वह और प्रधानमंत्री मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे। उन्होंने कहा था कि इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति की टिप्पणी का समर्थन करते हुए कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता से साझेदारी की असीमित संभावनाओं को खोलने में मदद मिलेगी। एक्स पर एक पोस्ट में, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी व्यापार वार्ता भारत-अमेरिका साझेदारी की असीम संभावनाओं को उजागर करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। हमारी टीमें इन चर्चाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रही हैं। मैं राष्ट्रपति ट्रम्प से बात करने के लिए भी उत्सुक हूं। हम दोनों देशों के लोगों के लिए एक उज्जवल और अधिक समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। अमेरिका द्वारा भारतीय आयात पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने के बाद बढ़े आर्थिक तनाव के कारण नई दिल्ली को वैश्विक अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ रहा है। इसमें रूसी कच्चे तेल की खरीद के कारण अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ भी शामिल है, जो वाशिंगटन के अनुसार, यूक्रेन के साथ संघर्ष में मास्को के प्रयासों को बढ़ावा देता है।

डीलरों पर न डाला जाए कंपनशेसन सेस का बोझ, ऑटोमोबाइल सेक्टर की सरकार से अपील

नई दिल्ली । फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (एफएडीए) ने सरकार से मुआवजा उपकर यानी कंपनशेसन सेस के मुद्दे पर स्पष्टता लाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इसका बोझ डीलरों पर नहीं पड़ा चाहिए, जो केवल वितरण शृंखला का हिस्सा है। FAD के अध्यक्ष सीएस विग्नेश्वर ने कहा कि ऑटो निर्माता और एफएडीए दोनों जीएसटी कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। विग्नेश्वर ने बताया कि फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती मुआवजा उपकर को लेकर है। उन्होंने कहा कि हम पिछले हफ्ते से सरकार और अलग-अलग विभागों से इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। असल में मुआवजा उपकर अंतिम उपभोक्ता द्वारा ही चुकाया जाना था, और यही अब मुख्य अड़चन बन गया है। उन्होंने कहा कि हम लॉजिस्टिक्स और पूरे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का हिस्सा हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा अगर मुआवजा उपकर का बोझ हम पर डाला जाए। सरकार को इस अस्पष्टता को दूर कर न्यायसंगत समाधान लाना चाहिए, जिससे सभी को फायदा हो। 22 सितंबर को संचित क्षतिपूर्ति उपकर समाप्त हो जाएगा, और ऑटो कंपनियां डीलरों के पास बचे स्टॉक पर लगने वाले उपकर के बारे में वित्त मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांग रही हैं। वे या तो इसे अपनी कर देनदारी में समायोजित करने की अनुमति देने या सरकार से रिफंड की मांग कर रही हैं। 22 सितंबर से ऑटोमोबाइल्स पर मुआवजा उपकर समाप्त हो जाएगा। फिलहाल वाहनों पर 28फीसदी जीएसटी लागू है और इसके अलावा गाड़ियों के प्रकार के अनुसार छोटी कारों पर 1फीसदी से लेकर एसयूवी पर 22फीसदी तक का मुआवजा उपकर लगाया जाता है। यह उपकर जीएसटी लागू होने के बाद शुरुआती पांच साल तक राज्यों के राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए लगाया गया था। हालांकि कोविड-19 के दौरान राजस्व में कमी पूरी करने के लिए इसकी अवधि को बढ़ा दिया गया था। साथ ही 1,200 सीसी और 1,500 सीसी तक की इंजन क्षमता वाली पेट्रोल और डीजल कारों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। वहीं इससे अधिक क्षमता वाली कारों पर अधिकतम 40 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

सेबी बोर्ड की बैठक शुक्रवार को, तुहिन कांत की अध्यक्षता में नियामकीय सुधारों पर होगी चर्चा

नई दिल्ली ।

बाजार नियामक सेबी के निदेशक मंडल की शुक्रवार को होने वाली अपनी बैठक में कई नियामकीय सुधारों पर चर्चा होगी। सूत्रों के अनुसार इन सुधारों में कंपनियों के लिए न्यूनतम आईपीओ आवश्यकताओं में ढील देना और न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों को पूरा करने के लिए समयसीमा को बढ़ाना शामिल है। उन्होंने बताया कि एजेंडे में अन्य प्रमुख मदों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए अनुपालन को सरल बनाना, कुछ वैकल्पिक निवेश कोषों (एआईएफ) में मान्यता प्राप्त निवेशकों के लिए विनियमन में ढील देना, रेटिंग एजेंसियों की गतिविधियों का दायरा बढ़ाना और आरईआईटी और इनविट को इक्विटी का दर्जा देना शामिल है।

इनमें से कई प्रस्ताव पहले ही सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रस्तुत किए जा चुके हैं, जो विनियामक परिदृश्य को परिष्कृत करने की दिशा में व्यापक प्रयास का संकेत देते हैं। यह तुहिन कांता पांडे की अध्यक्षता में तीसरी बोर्ड बैठक होगी, जिन्होंने 1 मार्च को पदभार ग्रहण किया था। बोर्ड बड़े जारीकर्ताओं को भारत में सूचीबद्धता के लिए प्रोत्साहित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकता है। प्रस्ताव के तहत, 50,000 करोड़ रुपये से 1 लाख करोड़ रुपये के बीच बाजार पूंजीकरण वाली कंपनियों के लिए, नया न्यूनतम सार्वजनिक प्रस्ताव (एमपीओ) 1,000 करोड़ रुपये करने की बात कही गई है। यह निर्गम-पश्चात पूंजी का कम से कम 8 प्रतिशत होगा। इसमें न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस) 25 प्रतिशत होगी। इसे वर्तमान तीन वर्षों के बजाय 5 वर्षों के भीतर हासिल किया जाना होगा। 1 लाख करोड़ रुपये से 5 लाख करोड़ रुपये के बीच बाजार पूंजीकरण वाले जारीकर्ताओं के लिए, एमपीओ 6,250 करोड़ रुपये और पोस्ट-इश्यू पूंजी का कम से कम 2.75 प्रतिशत होगा, एमपीएस की समय सीमा शेयरधारिता के स्तर के आधार पर 10 वर्ष तक बढ़ा दी जाएगी। 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक बाजार पूंजीकरण वाली कंपनियों के लिए प्रस्तावित एमपीओ 15,000 करोड़ रुपये का होगा और यह निर्गम-पश्चात पूंजी का कम से कम 1 प्रतिशत होगा, इसमें न्यूनतम 2.5 प्रतिशत का लिक्विडेशन हो होगा। बोर्ड भारतीय प्रतिभूति बाजार में भाग लेने के इच्छुक कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों के लिए एकल खिड़की पहुंच शुरू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे सकता है। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना और निवेश गंतव्य के रूप में देश के आकर्षण को बढ़ाना है।

घर बनाना होगा आसान, इतने रुपए सस्ती होंगी सीमेंट की बोरी!

बिजनेस डेस्क। जीएसटी दरों में किए गए बदलाव से सीमेंट की 50 किलो की बोरी के दाम में 30-35 रुपए तक की कमी आ सकती है जिससे निर्माण लागत कम हो जाएगी। बुधवार को एक रिपोर्ट में यह संभावना जताई गई। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जीएसटी दरों में कटौती का फैसला सीमेंट क्षेत्र के लिए संरचनात्मक रूप से सकारात्मक साबित होगा। पिछले हफ्ते जीएसटी परिषद ने मौजूदा चार-स्तरीय कर ढांचे को घटाकर पांच प्रतिशत एवं 18 प्रतिशत की दो दरों में बदलने का फैसला किया था। इस फैसले के अनुरूप 22 सितंबर से सीमेंट पर कर की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी जाएगी। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि प्रतिस्पर्धा के चलते कंपनियां इस लाभ को उपभोक्ताओं तक पहुंचाएंगी जिससे

कीमतों में नरमी आएगी और बुनियादी ढांचा एवं आवास परियोजनाओं की लागत घटेगी। हालांकि सीमेंट कंपनियों की वास्तविक प्रति बोरी आय एक दायरे में ही रहने की संभावना है। हालांकि एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष में सीमेंट की मांग में पांच से सात प्रतिशत वृद्धि का अनुमान बरकरार रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई-सितंबर तिमाही में मानसून की सक्रियता के कारण निर्माण गतिविधियां सुस्त रहने से मांग पर दबाव रह सकता है। शहरी क्षेत्रों में नई आवासीय परियोजनाओं की शुरुआत घटने से मांग कमजोर बनी हुई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर मानसून और वास्तविक मजदूरी वृद्धि से खपत मजबूत रहने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2025-26 की अप्रैल-जून तिमाही में सीमेंट उद्योग ने छह से सात प्रतिशत वृद्धि दर्ज की थी।

आतंकी साजिश नाकाम : दिल्ली पुलिस को मिली कामयाबी, पांच आतंकियों को किया गिरफ्तार; आईईडी बनाने की सामग्री बरामद

नई दिल्ली । दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी मॉड्यूल का खुलासा करते हुए कई राज्यों में छापेमारी के बाद पांच तीन और संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिससे गिरफ्तारियों की कुल संख्या पांच हो गई है। अन्य दो संदिग्धों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने आईईडी बनाने में इस्तेमाल होने वाले कुछ हिस्से भी बरामद किए हैं। सूत्रों ने बताया कि आरोपी कई सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से पाकिस्तान स्थित संचालकों के संपर्क में थे, जिनकी अब पुष्टि की जा रही है। दिल्ली पुलिस सूत्र के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने अलग-अलग राज्यों से पांच आतंकियों को गिरफ्तार किया है। दो दिल्ली से, एक मध्य प्रदेश से, एक हैदराबाद से और एक रांची से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आईईडी बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान भी बरामद किया है। जांचकर्ताओं के अनुसार, समूह का प्रमुख सदस्य असरार दानिश भारत से इस मॉड्यूल का संचालन कर रहा था और एन्क्रिप्टेड और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पाकिस्तान स्थित व्यक्तियों के साथ संपर्क बनाए हुए था। जांच से पता चला है कि संदिग्ध इन माध्यमों का इस्तेमाल भारत में युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और उन्हें अपने नेटवर्क में भर्ती करने के लिए करते थे। टीम के लीडर की आईडी गजवा लीडर थी और उसने अपना कोड नाम सीईओ रखा था। स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी प्रमोद सिंह कुशवाहा ने कहा, एक पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल का खुलासा किया गया है। 5 अलग-अलग राज्यों में कार्रवाई की गई है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। असरार दानिश, जो रांची का रहने वाला है, का मुख्य किरदार था। इसके साथ में 2 लोग मुंबई के थे-सूफियान अबुबकर और आफताब अंसारी। इनको दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। हुजैफ यमन को तेलंगाना के निजामाबाद से गिरफ्तार किया गया है। कामरान कुरैशी को मध्य प्रदेश के राजगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से काफी मात्रा में आईईडी बनाने की सामग्री और उपकरण बरामद किए गए हैं। कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं। इनको एक खिलाफत-स्टाइल का एक समूह तैयार करना था। साथ ही, उन्हें कुछ टारगेटेड किलिंग का काम सौंपा जाना था। असरार दानिश का हैंडलर एक पाक समर्थित हैंडलर है। इसमें आगे की जांच की जाएगी। जानकारी के मुताबिक, आईडी विस्फोट की साजिश रचने वाले इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएस) के तीन संदिग्ध आतंकवादियों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल (विशेष प्रकोष्ठ) ने संयुक्त कार्रवाई के दौरान दबोचा। झारखंड के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) और रांची पुलिस के साथ की गई इस कार्रवाई में असरार दानिश, अफताब और सूफियान को गिरफ्तार किया गया है जबकि पूछताछ के लिए आठ से ज्यादा संदिग्धों को उठाया गया था। पुलिस ने इनके कब्जे से बम बनाने वाली सामग्री, हथियार, सिमपेटेक केमिकल और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एक अधिकारी ने बताया कि बुधवार को बोकारो के रहने वाले मुख्य आरोपी असरार दानिश को रांची से गिरफ्तार किया गया है। वह इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक मॉड्यूल से संबंधित दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ओर दर्ज मुकदमे में वांछित था। स्पेशल सेल के एक वरिष्ठ सूत्र ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि तीनों इस्लामिक स्टेट से प्रेरित नेटवर्क के अन्य सदस्यों के संपर्क में थे और भारत में आतंकी संगठन के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाली गतिविधियों में शामिल थे। दानिश कई महीनों से सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर था।

भारत और मॉरीशस सिर्फ पार्टनर नहीं, परिवार - मोदी

वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (11 सितंबर) उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के एक दिवसीय दौरे पर हैं।

वाराणसी दौरे के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरीशस के अपने समकक्ष नवीनचंद्र रामगुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय वार्ता भी की। बाद में प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मोदी और रामगुलाम द्विपक्षीय सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिसमें विकास साझेदारी और क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे अपने संसदीय क्षेत्र में आपका स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। चीन काल से काशी भारत की सभ्यता और सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक रही है। हमारी संस्कृति और संस्कार सदियों पहले भारत से मॉरीशस पहुंचे और वहां की जीवन-पद्धति में रच-बस गए। काशी में मां गंगा की अविरल धारा की तरह, भारतीय संस्कृति का अविरल प्रवाह मॉरीशस को समृद्ध करता रहा है और आज, जब हम मॉरीशस के साथियों का काशी में स्वागत कर रहे हैं, तो यह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक मिलन है इसलिए मैं गर्व से कहता हूं कि भारत और मॉरीशस सिर्फ पार्टनर नहीं बल्कि एक परिवार है।

आप सांसद संजय सिंह हाउस अरेस्ट

श्रीनगर । आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह ने पार्टी विधायक मेहराज मलिक की गिरफ्तारी का विरोध किया किया है। संजय सिंह पार्टी विधायक के समर्थन में जम्मू-कश्मीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे इसे पहले ही पुलिस ने श्रीनगर के गेस्ट हाउस में नजरबंद कर दिया। संजय ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर बताया कि हमें शांतिपूर्ण धरना करने से रोका गया, मैं नगर के गेस्ट हाउस में नजरबंद हूं।

संजय सिंह से मिलने पहुंचे फारूख अब्दुल्ला

संजय सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारूख अब्दुल्ला उनसे मिलने सरकारी गेस्ट हाउस पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। संजय सिंह ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए कहा, अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री को भी मिलने की अनुमति नहीं है तो यह तानाशाही नहीं तो और क्या है? इस घटनाक्रम को लेकर विपक्षी दलों में नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं प्रशासनिक स्तर पर अब तक आधिकारिक तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया है। बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में जम्मू-कश्मीर में विपक्षी नेताओं की गतिविधियों पर रोक और नजरबंदी जैसे आरोप लगातार लगते रहे हैं। इस ताजा प्रकरण ने एक बार फिर पार्टी की सियासत को गरमा दिया है। पीएसए लगाना सौ फीसदी गलत है। सिंह ने कहा, ''आतंकवादियों के खिलाफ इस्तेमाल की जाने वाली धारा एक निर्वाचित सदस्य पर अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लिए आवाज उठाने के लिए लगाई गई है। यह बहुत गलत है। उन्होंने कहा, ''हम इस अन्याय के खिलाफ सड़कों पर, संसद में और यदि आवश्यक हुआ तो उच्चतम न्यायालय में लड़ेंगे।

डोडा में संदिग्ध धमाके से हड़कंप, पुलिस-एफएसएल जांच में जुटी

जम्मू । जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में गुरुवार को एक संदिग्ध विस्फोट हुआ, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। अधिकारियों के अनुसार, यह विस्फोट जमाई मस्जिद के पास डुम्री मोहल्ला में हुआ। जम्मू-कश्मीर पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जांच जारी है। पुलिस ने विस्फोट के सिलसिले में दो लोगों को हिरासत में भी लिया है। आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मेहराज मलिक, जो जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पार्टी के एकमात्र विधायक हैं, की गिरफ्तारी के बाद डोडा जिले में तनाव बढ़ गया है।

जम्मू-कश्मीर में गरमाई सियासत

विधायक मेहराज की गिरफ्तारी पर करने वाले थे प्रेस कॉन्फ्रेंस

दमनकारी रणनीति अपना रही बीजेपी- संजय सिंह का आरोप

उन्होंने भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर दमनकारी रणनीति अपनाकर 'आप को निशाना बनाने का आरोप लगाया। सिंह ने कहा, ''उन्होंने पहले अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और मुझे भी जेल में डाला है। आज मेहराज मलिक को भी जेल में डाल दिया गया है। 'आप नेता ने कहा कि वे पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने और ''राजनीतिक उत्पीड़न के खिलाफ प्रदर्शन में अगले कदम की रणनीति बनाने के लिए जम्मू में हैं। मलिक को हिरासत में लिये जाने के खिलाफ मंगलवार को डोडा और जम्मू-कश्मीर के अन्य स्थानों पर हुए प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में दो अधिकारियों समेत कम से कम आठ पुलिसकर्मी घायल हो गये थे।

केजरीवाल ने एक पोस्ट शेयर करते हुए जम्मू-कश्मीर पुलिस की कार्रवाई को गुंडागर्दी और तानाशाही बताया। आप संयोजक ने लिखा, पूर्व मुख्यमंत्री, जो वर्तमान मुख्यमंत्री के पिता हैं, को अपने ही राज्य में संजय सिंह से मिलने नहीं दिया जा रहा है? यह सरासर गुंडागर्दी और तानाशाही है।

जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह वास्तविकता है कि संजय सिंह को जेल में बंद किया गया था। बार-बार ऐसी चीजें की जा रही हैं। ऐसा कहा जाता है कि जम्मू-कश्मीर में सब कुछ ठीक है और एक नया जम्मू उभर रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वे हमेशा हमारे खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हैं।

गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र का अतिरिक्त कार्यभार

नई दिल्ली । भारत के नए उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन ने महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से गुरुवार को इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति भवन की तरफ से बयान जारी कर यह जानकारी दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने राधाकृष्णन के इस्तीफे के बाद गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। वे अब दोनों राज्यों के राज्यपाल की जिम्मेदारी संभालेंगे। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी बयान में आगे बताया गया कि सीपी राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल का पद खाली हुआ। इसके चलते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है।

हाइड्रोजन बम आएगा तो सब साफ हो जाएगा- राहुल गांधी

कांग्रेस सांसद का आरोप, चुनाव आयोग ने एक करोड़ फर्जी वोट बढ़ाए

रायबरेली ।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी दो दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में हैं। बृहस्पतिवार को दिशा की बैठक में शामिल होने के बाद जब वो बाहर निकले तो मीडिया को बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग बहुत आंदोलित हो रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जब हाइड्रोजन बम आएगा तो सब साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में वोट चोरी करके सरकारें बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक के चुनाव में वोट चोरी हुई है। हमने ब्लैक एंड व्हाइट सबूत दिए हैं। इंतजार कीजिए बहुत जल्द वोट चोरी के और खुलासे आने वाले हैं। भाजपा वाले परेशान न हों, वोट चोरी का हाइड्रोजन बम आने वाला है। सारा सब कुछ साफ हो जाएगा। राहुल गांधी बुधवार शाम ऊंचाहार पहुंचे। वहां बूथ अध्यक्षों से मिलकर लोकसभा चुनाव में भारी मतों के अंतर से जीत दिलाने के लिए धन्यवाद दिया। इस दौरान उनके निशाने पर चुनाव आयोग रहा। उन्होंने कहा कि भाजपा वोट चोरी कर चुनाव जीती है। लोकसभा चुनाव के बाद चुनाव आयोग ने देश में एक करोड़ फर्जी वोट बढ़ाए हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के बल पर ही कांग्रेस आगे बढ़ रही है। हम आप सभी के बदौलत परिवर्तन करेंगे। एक रेस्टोरेंट में आयोजित कार्यक्रम में राहुल गांधी के पहुंचते ही कांग्रेस पदाधिकारियों, प्रदेश सचिव अतुल सिंह ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। मंच पर पहुंचते ही पूर्व विधायक अजय पाल सिंह ने संविधान की किताब भेंट की। राहुल गांधी ने अपने वोट चोर गद्दी छोड़ मिशन पर कार्यकर्ताओं में जोश भरा और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगवाए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के विधानसभा चुनाव से चुनाव आयोग की मिलीभगत से भाजपा की वोट चोरी पकड़ी गई है। इस कारण भाजपा परेशान है। कहा कि इस सरकार में संविधान खतरे में है। हमारे अधिकारों को कुचलने की कोशिश की जा रही है। कार्यक्रम के बाद राहुल गांधी एनटीपीसी परियोजना के वीआईपी गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां वह रात्रि विश्राम करेंगे।

वोट चोरी के विस्फोटक सबूत देंगे-राहुल

दुनिया में बजेगा नारी शक्ति का डंका!

राजनाथ सिंह ने रवाना किया समुद्र प्रदक्षिणा

'साउथ ब्लॉक से अपने संबोधन में, रक्षा मंत्री ने इस यात्रा को नारी शक्ति, तीनों सेनाओं की सामूहिक शक्ति, एकता और संयुक्तता, आत्मनिर्भर भारत और उसकी सैन्य कूटनीति और वैश्विक दृष्टिकोण का एक ज्वलंत प्रतीक बताया।

मुंबई ।

नारी शक्ति और विकसित भारत के विजन को याद करते हुए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से दुनिया के पहले ऐतिहासिक त्रि-सेवा महिला परिक्रमा नौकायन अभियान, समुद्र प्रदक्षिणा को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साउथ ब्लॉक से अपने संबोधन में, रक्षा मंत्री ने इस यात्रा को नारी शक्ति, तीनों सेनाओं की सामूहिक शक्ति, एकता और संयुक्तता, आत्मनिर्भर भारत और उसकी सैन्य कूटनीति और वैश्विक दृष्टिकोण का एक ज्वलंत प्रतीक बताया। अगले नौ महीनों में, 10 महिला अधिकारी स्वदेश निर्मित भारतीय सेना नौकायन पोत त्रिवेणी पर सवार होकर लगभग 26,000 समुद्री मील की दूरी तय करते हुए पूर्वी मार्ग पर यात्रा करेंगी। वे भूमध्य रेखा को दो बार पार करेंगी, तीन महान अंतरीपों - लीउविन, हॉर्न और गुड होप - का चक्कर लगाते हुए सभी प्रमुख महासागरों और दक्षिणी महासागर और ड्रेक पैसेज सहित कुछ सबसे खतरनाक जलक्षेत्रों को कवर करेंगी। मई 2026 में मुंबई लौटने से पहले टीम चार अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों का दौरा भी करेगी।

राजनाथ सिंह ने समुद्र प्रदक्षिणा को न केवल एक जहाज पर की जाने वाली यात्रा, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना और अनुशासन व दृढ़ संकल्प की यात्रा भी बताया। उन्होंने कहा, अभियान के दौरान, हमारे अधिकारियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उनके दृढ़ संकल्प की लौ अंधकार को चीरती रहेगी। वे सुरक्षित घर लौटेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि भारतीय महिलाओं का पराक्रम किसी भी सीमा से परे है। रक्षा मंत्री सिंह ने हाल ही में दो भारतीय महिला नौसेना अधिकारियों लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए द्वारा हासिल की गई असाधारण उपलब्धि को याद किया, जिन्होंने साहस और समर्पण के साथ कई चुनौतियों का सामना करते हुए, एक अन्य स्वदेशी पोत, आईएनएस तारिणी पर सवार होकर, सफलतापूर्वक दुनिया की परिक्रमा की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आईएएसवी त्रिवेणी समुद्री साहसिक कार्य में एक और वैश्विक मानक स्थापित करेगी और भारत की समुद्री यात्रा में एक और स्वर्णिम अध्याय लिखेगी।

सोनिया गांधी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग खारिज

नागरिकता मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट का बड़ा फैसला

नई दिल्ली ।

कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी को गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत से राहत मिली, जिसने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनका नाम भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से तीन साल पहले मतदाता सूची में शामिल था। यह याचिका विकास त्रिपाठी नामक शख्स ने दायर की थी, जिसमें सोनिया गांधी पर फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने का आरोप लगाया गया था।

शिकायत के अनुसार, मूल रूप से इतालवी नागरिक सोनिया गांधी 30 अप्रैल, 1983 को नागरिकता अधिनियम की धारा 5 के तहत भारतीय नागरिक बन गईं। हालांकि, उनका नाम 1981-82 में ही नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल हो गया था, जिससे उस समय चुनाव आयोग को सौंपे गए दस्तावेजों पर सवाल उठे। अधिवक्ता नारंग ने बताया कि सोनिया गांधी का नाम, उनके दिवंगत देवर संजय गांधी के साथ, 1982 में मतदाता सूची से हटा दिया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह का विलोपन दर्शाता है कि मतदाता सूची में उनका पूर्व प्रवेश अनियमित था, क्योंकि केवल भारतीय नागरिक ही मतदाता के रूप में नामांकित होने के पात्र हैं। दस्तावेजों का हवाला देते हुए, नारंग ने कहा कि नागरिकता प्रदान किए जाने से पहले मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज कराने के लिए जाली या झूठे दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है। उन्होंने अदालत को बताया, -एक सार्वजनिक प्राधिकरण को गुमराह किया गया है, और धोखाधड़ी हुई प्रतीत होती है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि दिल्ली पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद, कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे याचिकाकर्ता के पास अदालत का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। इसलिए, याचिका में प्राथमिकी दर्ज करने और कथित अपराधों की जांच के निर्देश देने की मांग की गई है।

एक ही परिवार के 4 लोगों की खौफनाक हत्या!

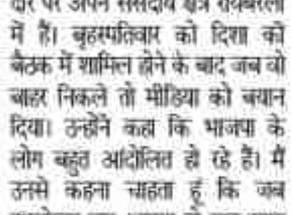

रायगढ़ । छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में दिल दहला देने वाली एक बेहद खौफनाक घटना सामने आई है। जहां एक ही परिवार के 4 लोगों का बेरहमी से हत्या के बाद दफनाए जाने की आशंका है। घटना जिले के खरसिया थाना क्षेत्र के तुसेकेला गांव के राजीव नगर मोहल्ले की है। शुक्रवार को घर से बदबू आने से लोगों को घटना की जानकारी लगी। इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों ने तुरंत पुलिस को टीम को सूचना दी। पुलिस के अनुसार, मृतक बुधराम उरांव पिता चमार सिंह के परिवार के सदस्य कई दिनों से लापता थे। मोहल्ले में बंद पड़े घर से तेज दुर्गंध आने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दरवाजा खुलवाकर जब भीतर देखा तो दीवारों और फर्श पर खून के छींटे पाए गए, जिससे अंदेशा गहरा गया कि यहां किसी वीभत्स अपराध को अंजाम दिया गया है।

जेन-जेड का नया फैसला , सुशीला कार्की नहीं.. अब ये शख्स होगा नेपाल का पीएम

इंटरनैशनल डेस्क । नेपाल में जारी राजनीतिक उथल-पुथल और जनरेशन-जेड के नेतृत्व में हो रहे हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच अब एक नई राजनीतिक दिशा सामने आ रही है। दरअसल, नेपाल विद्युत प्राधिकरण के पूर्व प्रमुख इंजीनियर कुलमान घिसिंग को अंतरिम सरकार का नेतृत्व सौंपे जाने की चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक, शुरू में जेन-जेड गुट की ओर से देश की अंतरिम सत्ता के लिए पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की का नाम प्रस्तावित किया गया था, लेकिन उनके नाम को लेकर गुट के भीतर विरोध उत्पन्न हो गया। इसके बाद कुलमान घिसिंग का नाम सर्वसम्मति से आगे लाया गया है। जेन-जेड गुट की ओर से जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, संविधान के अनुसार, पूर्व प्रधान न्यायाधीश और न्यायाधीश इस पद के लिए योग्य नहीं होते। साथ ही, सुशीला कार्की की उम्र 70 वर्ष से अधिक है, इसलिए वे जेन-जेड का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकतीं। इसी कारण उनका नाम अस्वीकृत किया गया है।

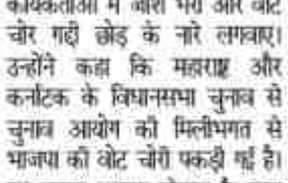

विज्ञप्ति में यह भी उल्लेख किया गया है कि बालेन्द्र शाह (वर्तमान में काठमांडू के मेयर) ने इस पद में रुचि नहीं दिखाई। हर्क साम्पाङ (धरान के मेयर) के बारे में कहा गया कि वे सर्वमान्य नेतृत्व नहीं बन सकते और सुशीला कार्की को संवैधानिक व आयुसीमा के कारण अयोग्य माना गया।

एशिया कप/ खून और क्रिकेट साथ-साथ कैसे चलेंगे? भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर शिवसेना ने दी प्रदर्शन की चेतावनी

मुंबई । एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को लेकर देश में सियासी पारा चरम पर है। इसे लेकर शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने कहा, ...हम इस भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच का विरोध करेंगे। महिलाएं सड़कों पर उतरेंगी और हमारा अभियान सिंदूर रक्षा अभियान है... आपने कहा था कि पानी और खून साथ-साथ नहीं बहेंगे। अगर पानी और खून साथ-साथ नहीं बहेंगे, तो खून और क्रिकेट साथ-साथ कैसे चलेंगे? यह देशद्रोह है, बेशर्मी है। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, यह अभी भी जारी है। पहलगाम में हमारी 26 महिलाओं का सिंदूर मिटा दिया गया। उनका दर्द, दुख और गुस्सा खत्म नहीं हुआ है। आज भी वे सदमे में हैं। आप लोग अबू धाबी में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। यह बेशर्मी है, यह देशद्रोह है। मेरा सवाल भाजपा से है, सरकार से नहीं। मेरा सवाल विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल से है। इसमें आपकी कोई भूमिका है या नहीं? इससे पहले उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एशिया कप में संभावित भारत-पाकिस्तान मैच के देश में सीधे प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की थी। उन्होंने पिछले महीने ही राष्ट्रीय हित और जनभावना का हवाला देते हुए मैच का सीधा प्रसारण बंद करने के लिए सरकार को पत्र लिखा था।

मेरे खिलाफ पैसे देकर चलाया जा रहा राजनीतिक अभियान -नितिन गडकरी

नागपुर ।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि ई20 मिश्रित ईंधन के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा अभियान मुझे राजनीतिक रूप से निशाना बनाने के लिए है। इसे पैसे देकर चलाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के वार्षिक सम्मेलन में सवालों के जवाब दे रहे थे। वहां उनसे पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण से जुड़ी चिंताओं के बारे में पूछा गया था। गडकरी ने जवाब दिया कि ऑटोमोबाइल निर्माता और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया जैसी संस्थाओं ने पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण पर अपने निष्कर्ष साझा किए हैं। मंत्री ने कहा, जिस तरह आपका उद्योग काम करता है, उसी तरह राजनीति भी काम करती है। सोशल मीडिया अभियान सशुल्क था। यह मुझे राजनीतिक रूप से निशाना बनाने के लिए था। इसमें कोई तथ्य नहीं है। सब कुछ स्पष्ट है। इथेनॉल मिश्रण आयात का विकल्प, लागत-प्रभावी, प्रदूषण-मुक्त और स्वदेशी है। गडकरी ने कहा कि भारत जीवाश्म ईंधन के आयात पर भारी रकम खर्च करता है। उन्होंने पूछा कि क्या जीवाश्म ईंधन के आयात को कम करने और बचाई गई राशि को भारतीय अर्थव्यवस्था में लगाने का प्रयास करना आर्थिक रूप से एक अच्छा कदम नहीं है। उन्होंने कहा, हमने मक्का से इथेनॉल बनाया। इस कदम से किसानों को 45,000 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है।

सिंगापुर जाने वाले एअर इंडिया के विमान में आई तकनीकी खामी, छह घंटे देरी से भरी उड़ान

दिल्ली। सिंगापुर जाने वाले एयर इंडिया के एक विमान में सवार 200 से अधिक यात्रियों को बुधवार रात दिल्ली हवाई अड्डे पर परेशानी का सामना करना पड़ा। विमान में एयर कंडीशनिंग सिस्टम और इलेक्ट्रिक सप्लाई में खराबी के चलते यात्रियों को फ्लाइट से उतार दिया गया। लगभग छह घंटे की देरी के बाद उन्हें उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। गुरुवार को एयर इंडिया ने कहा कि दिल्ली से सिंगापुर जाने विमान के केबिन में कूलिंग संबंधी समस्या के कारण उड़ान में देरी हुई। यात्रियों को देरी के बारे में नियमित रूप से सूचित किया जाता रहा और दिल्ली में ग्राउंड स्टाफ ने हवाई अड्डे पर यात्रियों को जलपान और भोजन सहित हर संभव सहायता प्रदान की।